Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged prevalence of corruption in implementation of Central Government Schemes.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद ।

इस देश में स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम से, आम लोगों के लिए, उन्होंने यहां पर एक बड़ा अच्छा कानून पेश किया था, आज हम उनको बधाई देना चाहते हैं और उनके प्रति नमन भी करना चाहते हैं । संविधान का 73वां और 74वां संशोधन हुआ था, जिसमें पंचायतों को अधिकार दिया गया था । इन्होंने जो कानून पास किया था, वह आर्टिकल 243-ई और 243-यू है । मैं झारखंड राज्य से आता हूं, वहां इन दोनों का जबरदस्त वाइलेशन हुआ है ।

महोदय, पिछले एक साल से झारखंड राज्य में पंचायत/म्यूनिसिपिल कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं हुआ है ।...(व्यवधान) हमारे बगल में बिहार राज्य है, वहां कोरोना के बावजूद भी चुनाव हुआ । हमारे बगल में पश्चिम बंगाल राज्य भी है, जहां पर कोरोना के बावजूद भी चुनाव हुआ । लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि इसमें 243-ई और 243-यू आर्टिकल का वाइलेशन हुआ है, जो वर्तमान मुखिया थे या जिला परिषद के अध्यक्ष थे, उन्हीं को ही कंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि संविधान के तौर पर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं ।

झारखंड कांग्रेस शासित राज्य है । उसके पीछे जो कारण है, जो मुखिया है, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, वहां केन्द्र की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वह वित्त आयोग का पैसा हो, चाहे वह मनरेगा का पैसा हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा हो, चाहे स्वास्थ्य का पैसा हो, चाहे बिजली का पैसा हो या चाहे वह किसी भी प्रकार का पैसा हो, सारे पैसों में कमीशन बटा हुआ है । चाहे कोयले का कमीशन हो, चाहे बालू का कमीशन हो, चाहे आयरन ओर का कमीशन हो, चाहे पोस्टिंग-ट्रांसफर हो । इस मुखिया के माध्यम से, चूंकि संविधान के आर्टिकल के वाइलेशन के बाद मुखिया को कंटिन्यू किया गया है, सभी से राज्य सरकार एक सर्टन कमीशन ले रही है ।

महोदय, मेरा आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से यह आग्रह है कि केन्द्र का जितना पैसा आबंटित है, क्योंकि आज स्वर्गीय राजीव गांधी जी की आत्मा रो रही होगी कि हमने इस तरह का कानून पास किया है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस शासित राज्य में ऐसा हो रहा है । केन्द्र के सभी पैसों को रोकना चाहिए, सीबीआई की इन्क्वॉयरी होनी चाहिए, इसमें जो भी दोषी हैं, उनको जेल भेजना चाहिए और झारखंड राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए ।...(व्यवधान)